Water Dispute between India and Bangladesh

1732. SHRI PRAMOD MAHAJAN:
SHRI VIREN J. SHAH:

Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state:

(a) to what extent Bangladesh has responded to its obligation to cooperate in the optimum utilisation of water resources as available in Ganga and Brahmputra to both the countries in accordance with the international practice;

(b) to what extent Bangladesh has broken the string of bilateral agreements the latest being the one signed between the Prime Ministers of both the countries in May, 1992;

(c) what is the present position in this regard; and

(d) how Government propose to work out any solution to augment the Ganga flow by diverting the Brahmaputra when the Bangladesh is unwilling to cooperate with India?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT AND THE MINISTRY OF WATER RESOURCES (SHRI P. K. THUNGON): (a) to (d) Pursuant to the understanding reached between Bangladesh and India at the Prime Minister's level in May 1992 an Indo-Bangladesh Joint Committee of Experts was constituted to work for an equitable, long term and comprehensive arrangement for sharing the flows of the major rivers. Contrary to this understanding, Bangladesh started systematic internationalisation of the water sharing issue about a year back to generate pressure on India and arrive at a settlement of its choice. Bangladesh is yet to respond to our proposal for augmenting the lean season flow of Ganga by diverting the surplus waters of Brahmaputra. India would however, continue to persuade Bangladesh and seek their cooperation in resolving the water sharing issue as per the understanding of May, 1992.

सरदार सरोवर परियोजना

1733. **श्री दिलीप सिंह जूदेव :**
श्री रजनी रंजन साहू :
श्रीमती वीणा वर्मा :
श्री एन. गिरि प्रसाद:
श्री चतुरानन मिश्र :
डा० बापू कालदाते :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरदार सरोवर परियोजना का निर्माण कार्य निर्धारित समय सीमा के अनुसार चल रहा है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या परियोजना के कार्य की समीक्षा करने हेतु सरकार द्वारा गठित "पांच सदस्यीय दल" ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(घ) यदि हां, तो उसकी मुख्य सिफारिशें क्या-क्या हैं ;

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का विचार है ;

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(छ) प्रतिवेदन के कब तक प्रस्तुत कर दिए जाने की संभावना है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री और जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन) : (क) और (ख) नदी तल विद्युत घर, जिसका कार्य जापान से टरबो जेनरेटिंग सेटों को खरीदने में हो रहे विलम्ब के कारण पिछड़ रहा है, को छोड़कर सरदार सरोवर परियोजना का निर्माण कार्य निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चल रहा है ।